भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पहलगाम हमले के विरोध में आतंकवादियों का पुतला फूंका

कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के खिलाफ आज राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया।

जयपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक गोपाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्टैचू सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला और दो मिनिट का मौन रखा।

जयपुर। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के खिलाफ आज राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान के झंडे को जलाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्दोष नागरिकों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर नारेबाजी की।

प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा, "आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत इसकी हर

- **सर्व मुस्लिम समाज ने एकजुटता दिखाते हुए आतंकी हमले का किया विरोध**

सूरत में निंदा करता है और इससे सख्ती से निपटेगा।" उन्होंने आगे कहा कि "भारत में हिंदू और मुस्लिम एक हैं। आज पूरा मुस्लिम समाज अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। यही एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।"

हमीद खान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सभी द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवाद को संरक्षण देने के चलते लिया गया है। उन्होंने बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों में आतंकवाद के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया, शहीदों के लिए दुआएं की गईं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे जलाए गए। मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की।

इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम. सादिक खान, फिरोज़ खान (पूर्व प्रदेश महामंत्री), हिदायत खान, मुनव्वर खान, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रेशमा हुसैन, जयपुर शहर अध्यक्ष अब्दुल अज़ीज़, शहर महामंत्री परवेज़ खान, मजीद पठान, मोहम्मद इरशाद खान, उस्मान चौहान, फरमान अहमद, तथा ऋषभ जैन सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आरएएस पद के लिए अपात्र घोषित करने वाला 24 साल पुराना आदेश रद्द

- **राज्य सरकार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाकर आरएएस पद पर नियुक्ति के आदेश**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-1999 और 2003 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को अनफिट करने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को 21 अप्रैल, 2006 से समस्त बकाया, वरिष्ठता और पदोन्नित के साथ आरएएस पद पर नियुक्ति देने को कहा है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता के पेंशन व अन्य परिलाभों के लिए सेवाकाल की गणना सितंबर, 2001 से करने को कहा है। अदालत ने कहा कि योग्यता की स्वीकृति के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में याचिकाकर्ता की आरएएस पद पर नियुक्ति एक माह में राज्य के मुख्य सचिव की उपस्थिति में दी जाए। इसके अलावा अदालत ने लंबे समय पर याचिकाकर्ता के साथ हुए भेदभाव को देखते हुए राज्य सरकार पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. देवाराम शिवरान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता एसपी शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने आरएएस भर्ती-1999 में भाग लेकर मेरिट में 360वां स्थान प्राप्त किया था। वहीं उसे आंखों का दोष बताकर मेडिकल अनफिट कर नियुक्ति से इनकार कर दिया। इसे चुनौती देने पर अदालत ने सितंबर, 2001 को याचिकाकर्ता के लिए एक पर रिक्त रखने को कहा। इसके बाद साल 2003 की आरएएस भर्ती में याचिकाकर्ता ने 21वां स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसे समान आधार पर अनफिट बताया गया। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर दूसरे मेडिकल बोर्ड ने परीक्षण किया और उसे अनफिट बता दिया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने मेरिट में 22वां स्थान रखने वाली अभ्यर्थी को आरएएस पद पर नियुक्ति दे दी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना के बाद मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित की और उसकी सिफारिश पर याचिकाकर्ता को लेखा सेवा में नियुक्ति दी गई। याचिका में कहा गया कि वह बीते दो दशक से लेखा सेवा में काम कर रहा है और शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। एकलपीठ ने उसके विधिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उसके लिए एक पर रिक्त रखने को कहा था। ऐसे में उसे आरएएस कैडर में नियुक्ति दी जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता दिव्यांग है और आरएएस व आईएएस भर्ती में साल 2005 व 2007 से दिव्यांग आरक्षण दिया जाने लगा है। इससे पूर्व की भर्तियों में दिव्यांग आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद उसके रिकॉर्ड को देखते हुए उसे राज्य सरकार ने शिथिलता देते हुए लेखा सेवा में नियुक्ति दी।

वर्ष 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये चरणबद्ध रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ना है : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने राज्य बजट 2024-25 के दौरान 10 संकल्प पेश किए थे। इन्हीं संकल्पों को आधार बनाते हुए विकसित राजस्थान की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिये विकास की चार थीम के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के आगामी बजट भी विकसित राजस्थान की संकल्पना का दर्पण होंगे। शर्मा ने कहा कि हमें वर्ष 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिकता तय करते हुए चरणबद्ध रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। इसके लिए सर्वप्रथम वर्ष 2030 तक के विकास का रोडमैप तैयार करते हुए हमें मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट को सरल भाषा में तैयार कर आमजन तक पहुंचाएं तथा उनके अमूल्य सुझाव प्राप्त कर उन्हें इस डॉक्यूमेंट में शामिल करें।

शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

कि राज्य का प्रत्येक नागरिक समर्पण भावना के साथ प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना योगदान देगा तभी हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें भौतिक विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए लक्ष्य तय करने होंगे। इसके लिए कार्ययोजना बनाते समय हमें भविष्य की आवश्यकताओं तथा जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों को ध्यान में रखना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश की समग्र विकास यात्रा में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के असंतुलन को दूर करते हुए हमें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है जिससे ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन रूके तथा शहरों पर बढ़ता दबाव कम हो। श्री शर्मा ने कहा कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं

- **'विजन डॉक्यूमेंट को सरल भाषा में तैयार कर आमजन तक पहुंचाएं'**
- **'गांवों से शहरों की तरफ पलायन रूके'**

सुनियोजित दोहन करते हुए विकास करें जिससे भावी पीढी को संसाधनों की कमी न हो।

शर्मा ने कहा कि बदलते समय और बढ़ती आबादी के साथ परिवहन क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में हमें सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करते हुए बेहतर यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने पीएचईडी से संबंधित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पानी के लिए हम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं, इसकी बचत ही आपूर्ति है। वर्षाजल का सुनियोजित प्रबंधन और भूमि की वाटर रिचार्ज क्षमता को बढाकर जल संकट से बचा जा सकता है। इस दौरान राज्य स्टीयरिंग कमेटी में शामिल विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्चाधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

हीट वेव को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश

जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की।

जयपुर। जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने गर्मी एवं हीटवेव के दौरान मौसमी बीमारियों को लेकर सभी चिकित्सा अधिकारियों को सभी चिकित्सालयों में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिये गए हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर ये निर्देश दिए।

कलक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को राजकीय चिकित्सालयों में दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों, चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं पंच गौरव के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने डीटीएफआई की बैठक में जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा कर कम टीकाकरण करने वाले ब्लॉक्स में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले में 24 अप्रैल को प्रारंभ हुए विश्व टीकाकरण सप्ताह पर चर्चा हुई जिसमे लाभार्थियों को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीके लगाए जाएंगे।

कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों पर चर्चा कर एंटी लार्वा गतिविधियों व लू तापघात से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंच गौरव अभियान के तहत उन्होंने सभी चिकित्सा संस्थानों पर अधिकाधिक प्रचार- प्रसार के निर्देश दिए। राजश्री योजना की द्वितीय किश्त अपडेट करने के निर्देश दिए।

निलंबित उप निरीक्षक मनीष कुमार मीना सेवा से बर्खास्त

जयपुर। निलंबित उप निरीक्षक मनीष कुमार मीना सीआईडी बीआई पोस्ट नाचना जैसलमेर हाल मुख्यालय सीआईडी (विशा) जयपुर निवासी ग्राम व पोस्ट दुलेतो की ढाणी इन्दावा तहसील लालसोट जिला दौसा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में आईजी इंटेलिजेंस डॉ विष्णु कान्त द्वारा निर्णय प्रसारित किया गया है।

आईजी डॉ विष्णु कान्त ने बताया कि राज्य विशेष शाखा में पदस्थापित उप निरीक्षक मनीष कुमार मीना 1 अप्रैल 2024 से डयूटी से स्वैच्छा पूर्वक अनुपस्थित चल रहा था। उप निरीक्षक को डयूटी पर उपस्थित होने के लिए बार-बार रिकॉल नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह डयूटी पर उपस्थित नही हुआ।

राज्य के नवगठित जिलों के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन

जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर नव गठित जिलों फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीग, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़ के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव भगवंत सिंह ने बताया कि जिले में प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर होंगे तथा जिला परिषद प्रमुख सह अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग व जल संसाधन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी प्राधिकरण के सदस्य होंगे तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।

उन्होंने बताया कि जिले से निर्वाचित लोकसभा सांसद, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक एवं जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी प्राधिकरण के स्थायी आमंत्रित होंगे। इसके अतिरिक्त जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विशेष परिस्थियों में आवश्यक समझे जाने पर किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही आवश्यक समझे जाने पर प्राधिकरण द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के अधीन विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को भी शामिल किया जा सकेगा।

खड़गे की जयपुर में संविधान बचाओ रैली की तैयारी बैठक

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जयपुर में 28 अप्रैल को प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली के लिये आज जयपुर शहर कांग्रेस कार्यालय रामचंद्र जी का मंदिर हवा महल के सामने जयपुर पर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक एआईसीसी सचिव राजस्थान प्रभारी पूनम पासवान के मुख्य आतिथ्य, जिला प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ एवं जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर आर तिवाडी के नेतृत्व में की गई। संगठन महासचिव सीताराम शर्मा नेहरू ने बताया कि जयपुर शहर के आठ विधानसभा के विधायक और विधायक प्रत्याशी और ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने विधानसभा से एक 1000-1000 कार्यकर्ताओं में रैली में लाने का आश्वासन दिया।

योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिया जाये : डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

जयपुर। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं को प्लानिंग के साथ तय समयावधि में पूरा करे। योजनाओं द्वारा आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभान्वित किया जाये। किसी भी योजना

- **'बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्लानिंग के साथ तय समयावधि में पूरा करें'**

में किसी प्रकार का लीकेज न हो,सभी एक टीम भावना से कार्य करें,जिससे हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। ग्रामीण विकास मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेन्स नीति अपनाये जाने के निर्देश प्रदान किये।

डॉ.किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर के सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

डॉ.किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर के सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन संचालन के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि योजनाओं की निरंतर उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। ऐसे में अधिकारी अपने स्तर पर पूर्ण ईमानदारी व कत्तर्व्यनिष्ठा से कार्य समय पर पूरा करे।

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामुदायिक प्रकृति के कार्यो में लगे श्रमिकों की उपस्थिति नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) द्वारा की जा रही है। इस उपस्थिति की मॉनिटरिंग राज्य स्तर,जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर टीम गठित कर ऐप के माध्यम से की जा रही है,जिससे प्रतिदिन5से7लाख फर्जी श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगी है। एनएमएमएस के माध्यम से दर्ज की जा रही श्रमिक उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुए हैं। फर्जी श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगी है। कार्य स्थल पर वास्तव में उपस्थित श्रमिकों को ही भुगतान किया जा रहा है। नरेगा कार्यो में एनएमएमएस द्वारा की गई जांच में सर्वाधिक अनियमितता पाये जाने वाले12जिलों की130ग्राम पंचायतों में समितियां गठित कर जांच कराई जा रही है। इस तरह से एनएमएमएस राज्य स्तर,जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर जांच करने का नवाचार है,जिसकी भारत सरकार ने भी सराहना की है।

उन्होंने बताया कि राज्य की समस्त11214ग्राम पंचायतों में पंचायत पौधाशालाओं को विकसित करने हेतु2करोड़ से अधिक पौधे तैयार किये जा रहे है। पंचायत मॉडल फल वाटिका के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में एक-एक हजार पौधों की मॉडल पंचायत फल वाटिका विकसित की जा रही है,जिसमें पंचगौरव के तहत जिला विशेष फलों के पौधे लगाये जायेंगे,ताकि ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल संकुल तैयार किये जा रहे है,जिसमें सभी प्रकार के खेलों का समावेश किया जायेगा। सेना भर्ती परीक्षा की दक्षता हेतु आवश्यकतानुसार ट्रेक तैयार किये जा रहे है।

बैठक में हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत एवं ब्लॉक पौधारोपण की3स्टेज में की जा रही जियो टैगिंग पर चर्चा की गई। ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत पौधारोपण के1.03करोड़ एवं ब्लॉक स्तर पर पौधारोपण के2.07करोड़ पौधों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम की तर्ज पर ग्रामीण विकास,पंचायती राज विभाग एवं जल संग्रहण विकास को इस वर्ष संयुक्त रूप से2करोड़ पौधे लगाये जाने का लक्ष्य दिया गया है।

उन्होंने जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगाये गये सभी पौधों की पूरी देखभाल की जाये। गर्मियों में पानी की व्यवस्था करे और सभी पौधों को जियो टैग से जोड़ा जाये। सभी जिलों के अधिकारियों को7दिवस में गत वर्ष लगाये गये पौधों में से नष्ट हुए पौधों की रिपोर्ट बनाकर7दिवस के अंदर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

डॉ.किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और आतंकियों के मनोबल को तोड़ने का किया काम : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पहलगाम आतंकी हमले पर विरोध जताते हुए कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारना, यह आतंक की पराकाष्ठा है और भारत इसे कभी भी बर्दास्त नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। देश का प्रत्येक नागरिक आज उद्वेलित है और पीएम मोदी से आतंक को जड़ से समाप्त करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में पाक से किए गए समझौते को रद्द करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है।

राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान शुरू

- **'पहलगाम आतंकी हमले से देश उद्वेलित, भारत नहीं करेगा बर्दाश्त'**
- **'पाकिस्तान से किए गए समझौते रद्द करना पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला'**

से ही आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत में अस्थिरता पैदा करता आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, अब जल समझौता रद्द करने, बाघा बॉर्डर को बंद करने, आवागमन बंद करने और 48 घंटें में देश छोड़ने के आदेश जारी करने जैसे कड़े फैसले लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंकियों के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर पाक से समझौते रद्द करने का फैसला किया, वहीं दूसरी ओर सेना को भी सर्च और शुट करने के आदेश दे दिए। आतंकियों को पनाह देने वाले और सरंक्षण देने वालों पर भी सेना की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध का बदला लेकर रहेंगे। पूरे विश्व को आज पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा और ना ही उसकी विश्वसनियता बची। ऐसे में अब पाक से बात नहीं की जाएगी। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।